गतिशक्ति का आगाज : अब गति और शक्ति से समय पर पूरे होंगे सरकारी प्रोजेक्ट

दो रक्षा गलियारों समेत 1200 औद्योगिक समूह आपस में जुड़ेंगे

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब प्रोजेक्ट समय पर पूरे होंगे और अनावश्यक खर्च में कमी आएगी। उन्होंने बुधवार को बहुस्तरीय संपर्क के लिए 100 लाख करोड़ के राष्ट्रीय मास्टर प्लान 'पीएम गतिशक्ति' का शुभारंभ किया। यह योजना दो रक्षा गलियारों समेत 1200 से अधिक औद्योगिक समूहों को कई स्तर पर जोड़ेगी। इसका उद्देश्य लागत को कम करना व बुनियादी ढांचे का विकास है। यह रेल व सड़क सहित 16 मंत्रालयों को जोड़ने वाला एक डिजिटल मंच है।

पीएम मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ हम, अगले 25 सालों के भारत की बुनियाद रच रहे हैं। गतिशक्ति भारत के इसी आत्मबल, आत्मविश्वास को, आत्मनिर्भरता के संकल्प तक ले जाने वाला है। उन्होंने कहा कि गतिशक्ति के इस महाअभियान के केंद्र में हैं भारत के लोग, उद्योग, व्यापार जगत, उत्पादक और किसान। ये 21वीं सदी के भारत के निर्माण के लिए नई ऊर्जा देगा, उनके मार्ग की बाधा को खत्म करेगा। पीएम मोदी ने कहा, दुर्गा अष्टमी पर इसका शुभारंभ हुआ है और अब सारे प्रोजेक्ट समय पर पूरे होंगे। जेएएम यानी जनधन, आधार और मोबाइल ने सरकारी सुविधाओं की पहुंच को जिस तरह सुगम बनाया है। गतिशक्ति भी इसी तरह आधारभूत ढांचा के विकास के क्षेत्र में क्रांति लाएगी। >> पूर्व सरकारों में विकास कार्यों की रही सुस्त रफ्तार : पेज 13

>> गति और शक्ति : संपादकीय

अगले 25 सालों की बुनियाद

100

लाख करोड़ की गतिशक्ति योजना

200 से ज्यादा हेलीपैड हवाईअड्डे और वाटर एयरोड्रोम 4-5 साल में

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि आने वाले 4-5 साल में देश में 200 से ज्यादा नए एयरपोर्ट, हेलीपैड और वाटर एयरोड्रोम बनने जा रहे हैं। ये लक्ष्य आसान नहीं हैं, इन्हें पूरा करने के लिए असाधारण काम करना होगा।

'कार्य प्रगति पर' का बोर्ड बन गया था अविश्वास का प्रतीक

पहले हर कहीं 'वर्क इन प्रोग्रेस' या कार्य प्रगति पर है, का बोर्ड दरअसल अविश्वास का प्रतीक बन गया था। लोगों को किसी भी परियोजना के पूरे होने को लेकर भरोसा नहीं था। लेकिन तेजी से विकास के लिए गति, उत्साह और सामूहिक प्रयास की जरूरत होती है। पर अब यह सोच बदल रही है। पुराना ढर्रा पीछे छूट गया है। **-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री**

यूपी में नया रक्षा गलियारा

- सरकार का लक्ष्य 2025 तक 11 औद्योगिक गलियारे व तमिलनाडु-यूपी में दो नए रक्षा गलियारे
- सभी गांवों में 4जी संपर्क
- नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाकर 225 गीगावाट करना
- राष्ट्रीय राजमार्ग का 2 लाख किमी विस्तार
- प्रसारण नेटवर्क 4,54,200 सर्किट किमी
- 17000 किमी गैस पाइपलाइन का विस्तार।